International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN :2581-9925(Online), Impact Factor: 7.555, Volume 07, No. 04(III), October - December, 2025, pp. 59-63

राजस्थान में उद्योग और औद्योगिक विकास

डॉ. जगदीश प्रसाद मीना*

सह आचार्य ई. ए. एफ. एम., स्व. राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय बाँदीकुई, दौसा, राजस्थान।

*Corresponding Author: drjpmeena1973@gmail.com

Citation: मीना, जगदीश. (2025). राजस्थान में उद्योग और औद्योगिक विकास. International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science, 07(04(III)), 59–63.

सार

राजस्थान एक पिछड़ा हुआ एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश है। भौगोलिक स्थिति की प्रतिकूलता, पानी का अभाव, विद्युत की कमी व आधारभूत संरचना के अभाव में यहाँ बड़े पैमाने के उद्योगों का बहुत कम विकास हुआ है। अतः राजस्थान की ग्रामीण जनता के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग एवं खादी उद्योग का विशेष महत्त्व है। ये उद्योग रोजगार, प्रादेशिक आय, औद्योगिक विकेन्द्रीकरण, स्थानीय संसाधनों के उपयोग, कम पूँजी, व तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता की दृष्टि से राजस्थान के लिए विशेष महत्त्व रखते हैं। किसी भी देश के औद्योगिक विकास में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। विकासशील राष्ट्र होने के कारण ये उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के मेरुदण्ड हैं। इन उद्योगों का हमारी अर्थव्यवस्था में प्राचीनकाल से ही महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। रोजगार की दृष्टि से इन उद्योगों का कृषि के बाद दूसरा महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पूँजी का अभाव, श्रम की अत्यधिक पूर्ति तथा तकनीकी ज्ञान का अभाव आदि के कारण इन उद्योगों का महत्त्व बढ़ा है। इन उद्योगों का अतीत बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। किन्तु ब्रिटिश काल में इन उद्योगों का इतना पतन हुआ है कि भारत में ये उद्योग समाप्त प्रायः हो गये। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् इन उद्योगों के विकास पर सरकार ने काफी ध्यान दिया है, फिर भी इन उद्योगों का आशातीत विकास नहीं हो पाया है। लघु एवं कुटीर उद्योगों में अंतर देखने को मिलता है। लघु उद्योग प्रायः आधुनिक क्षेत्र में आते हैं, जबकि कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग परम्परागत क्षेत्र में आते हैं। लघु उद्योग बहुधा ग्रामीण क्षेत्रों में पाये जाते हैं और स्थानीय कच्चे माल, स्थानीय दक्षताओं तथा स्थानीय माँग पर आधारित होते हैं, जबकि कुटीर उद्योगों में बहुधा पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। ये उद्योग स्थानीय व विदेशी दोनों प्रकार की माँग की पूर्ति कर सकते है। भारत में ग्रामीणों को रोजगार देने व लोगों की आय में वृद्धि की दृष्टि से कृषि के सहायक उद्योग धन्धों का समुचित विकास करना आवश्यक है। आजकल निर्धनता निवारण की दृष्टि से भी इन उद्योगों का महत्त्व बढ़ गया है। हमारे देश में MSME इकाइयाँ परम्परागत लघु क्षेत्र व आधुनिक लघु क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में पायी जाती हैं। परम्परागत लघु उद्योग में खादी, हथकरघा, खाद्य तेल, नारियल के रेशे से बने पदार्थ, चमड़ा उद्योग आदि सम्मिलित हैं। आधुनिक लघु उद्योगों में अनेक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयाँ जैसे–पम्प सैट, डीजल इंजन, विद्युत मोटर्स, घड़ियाँ, रेडियो, ट्रांजिस्टर, रेफ्रिजिरेटर, बिजली के पंखे, सिलाई मशीन, टेलिविजन सैट, बिजली के तार, बुनाई की मशीनें, प्लास्टिक व रबड़ की वस्तुएँ, मिक्सर ग्राइन्डर, टेपरिकॉर्डर, टेलिस्कोप, कैमरा, अनेक प्रकार के वैज्ञानिक औजार, घरेलू उपकरण, दवाइयाँ आदि आती हैं, जिनकी खपत देश व विदेश दोनों में होती है। इस प्रकार सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग का क्षेत्र विस्तृत है।

* *Copyright © 2025 by Author's and Licensed by Inspira. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में इन उद्योगों को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, क्योंकि इन्ही उद्योगों पर लाखों ग्रामवासियों तथा वनवासियों का आर्थिक जीवन निर्भर है।

शब्दकोशः *उद्योग, औद्योगिकरण, आधारभूत संरचना, परमपरागत अद्योग, औद्योगिक नीति वैश्वीकरण।*

प्रस्तावना

किसी भी देश का तीव्र गति से आर्थिक विकास करने के लिए उसका औद्योगीकरण आवश्यक है। औद्योगीकरण केवल उद्याोग–धन्धों के विकास में ही सहायक नहीं है, बल्कि उससे कृषि व्यापार, यातायात, विदेशी व्यापार, रोजगार राष्ट्रीय आय इत्यादि में विकास को भी प्रोत्साहन मिलता है। राज्य द्वारा औद्योगीकरण की स्वस्थ परम्पराएँ स्थापित करने, नियन्त्रण करने, मार्गदर्शन देने, नियमन करने एवं तीव्र विकास करने के लिए औधोगिक नीति की आवश्यकता होती है। किसी देश की ओद्योगिक नीति सरकार की एक सिद्धान्त है। देश के औद्योगिक विकास का ढाँचा तैयार कर, देश को स्वावलम्बों एवं सिद्धान्तों से प्रभावित होती है। औधोगिक नीति देश के ओद्योगिक विकास का ढाँचा तैयार कर देश को स्वावलम्बी एवं समृद्ध बनाने में सहायक होती है। इसलिए सरकार की औद्योगिक नीति सुपरिभाषित, स्पष्ट एवं प्रगतिशील होनी चाहिए तथा उसका निष्ठापूर्वक पालन किया जाना चाहिए।

राजस्थान भोगोलिक दृष्टि से भारत के पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। राज्य के प्राकृतिक साधनों की विपुलता एवं औद्योगिक क्षैत्र के सर्वोच्च साहसियो की जन्मस्थली होने के बावजूद आधारभूत संरचना के प्रभाव एवं आर्थिक पिछडेपन के कारण औधोगिक विकास में काफी पिछड़ गया। 1962 में राजस्थान में भारत की कुल पंजीकृत औद्योगिक फैक्टरियों का 1.6ः भाग तथा कुल फैक्टरी रोजगार का 1.5ः भाग था जबकि भारत के कुल औद्योगिक उत्पादन का केवल 1.1ः भाग ही राजस्थान में उत्पादित होता था, यह उसके भी औद्योगिक पिछड़ेपन की झलक देता था। राजस्थान में औद्योगिक विकास स्वतंत्रता के पूर्व काफी निम्न स्तर पर था। छोटे, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग–धन्धे अवश्य थे किन्तु बडी एवं मध्यम आकार की औद्योगिक इकाइयाँ नगन्य सी ही थीं इसका मुख्य कारण विदेशी शासन एवं सामंती शासन का होना था, जिसने औद्योगिक विकास हेतु बांछित वातावरण निर्माण एवं वांछित आधारभूत संरचना विकास पर समान्यतः ध्यान नहीं दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश चात् योजनाबद्ध विकास के माध्यम से राज्य में औद्योगिक विकास ने गति ग्रहण की है। प्रत्येक राज्य का एक उद्देश्य यह होता है कि वह जनता के सामने लोक कल्लाणकारी के रुप में प्रकट हो। सरकार आर्थिक विकास के गति को तेज करना चाहती है। जनता में व्याप्त गरीबी दूर करना चाहती है।

औद्योगिक विकास का महत्त्व एवं उसकी आवश्यकता

राज्य में औद्योगिक विकास की महत्ती आवश्यकता है। इस संबंध में औद्योगिक विकास के लाभों का निम्नवत उल्लेख प्रासंगिक है

- **रोजगार संबर्द्धन** – 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य के श्रमिकों का व्यावसायिक वर्गीकरण बतलाता है कि कुल श्रमिकों में से 70 प्रतिशत से अधिक तो कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में ही कार्यरत हैं। विनिर्माण विधायन सेवायें एवं मरम्मत कार्यों पर मात्र 7 प्रतिशत से कुछ ही अधिक श्रमिक कार्यरत हैं। कृषि क्षेत्र में रोजगार भी पूर्ण रोजगार नहीं होकर काफी सीमा तक अर्द्ध–रोजगार को सम्मिलित करता है। वहाँ रोजगार वृद्धि की *व्यावहारिक* रूप से कोई गुंजाइश नहीं है। अतः औद्योगिक विकास के माध्यम से ही बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये रोजगार के अवसर बढ़ाये जा सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में विकास से सेवा क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा ग्रामीण क्षेत्रों का अर्द्ध–रोजगार भी कम हो सकेगा।

- **राज्य आय में योगदान**– कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में इतनी अधिक जनसंख्या के कार्यरत होने के उपरान्त भी कृषि क्षेत्र का योगदान राज्य आय में आनुपातिक रूप से बहुत कम रहता है क्योंकि अधिकांशतः कृषि उत्पादन वर्षा पर निर्भर करता है एवं वर्षा अधिकांश वर्षों में खिलवाड़ ही कर जाती है। वर्ष 2005 के मूल्यों पर विभिन्न वर्षों में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का कुल शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद में योगदान 20 से 25 प्रतिशत के मध्य ही रहा है। हालांकि इसमें 70 प्रतिशत लोग संलग्न थे, जबकि विनिर्माणी क्षेत्र में बहुत कम प्रतिशत व्यक्तियों के कार्यरत रहने के उपरान्त भी इसका योगदान 30 प्रतिशत के लगभग रहता है। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने से निश्चित रूप से प्रत्यक्षतः एवं परोक्ष रूप से राज्य की आय में वृद्धि होगी एवं प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो सकेगी।
- **सरकारी संसाधनों में अभिवृद्धि** – औद्योगिक विकास के फलस्वरूप कर आदि के रूप में राज्य सरकार को अतिरिक्त आय होने से सरकार के पास विकास कार्यक्रमों के लिये संसाधन बढ़ जाने से नये विकास कार्य अधिक सहजता से संभव हो सकेंगे।
- **कृषि क्षेत्र के विकास में सहायता** – वस्तुतः समस्त क्षेत्र परस्पर एक–दूसरे पर निर्भर करते हैं। औद्योगिक विकास से कृषि के लिये आदान (inputs), यथा–उर्वरक एवं उपकरणों की उपलब्धि बढ़ पाने से कृषि क्षेत्र को भी लाभ होगा एवं कृषि उत्पादों के विपणन हेतु भो अवसर बढ़ेंगे।

राजस्थान में औद्योगिक विकास में बाधाएँ/समस्याएँ

यह दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान में जन्मे उद्योगपतियों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है पर वे अपने जन्म स्थान राजस्थान का औद्योगीकरण उतना नहीं कर पाये। राजस्थानी उद्योगपति बिरला, डालमिया, साहु–जैन, सिंघानिया, बांगड़, मोरारका, सेकसरिया, गोयनका, जयपुरिया आदि कुछ बाधाओं के कारण ही राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति प्रदान नहीं कर सके। इन कठिनाइयों को धीरे–धीरे दूर करने से ही तीव्र औद्योगीकरण संभव हुआ है। मुख्य बाधायें इस प्रकार है–

- **विद्युत शक्ति का अभाव** – उद्योगों के संचालन के लिये राजस्थान में शक्ति साधनों का नितान्त अभाव है। अतः उद्योगों की स्थापना प्रायः *मुश्किल* थी। जब भाखड़ा नांगल, चम्बल आदि से विद्युत शक्ति प्राप्त होने लगी तो कोटा, चित्तौड़, भरतपुर, जयपुर, फालना आदि स्थानों पर उद्योग स्थापित होने लगे। अब तो राणा प्रताप सागर बांध के निकट अणु भट्टी से बिजली प्रदान करने की व्यवस्था से कुल 4 लाख किलोवाट बिजली प्राप्त होगी। यद्यपि विद्युत विकास से उत्पादन 8 मेगावाट से बढ़कर 4100 मेगावाट हो गया है फिर भी मांग के मुकाबले विद्युत शक्ति कम पड़ती है।
- **पानी का अभाव** – राजस्थान एक शुष्क प्रदेश है, जहां वर्षा का औसत बहुत नीचा है। अकालों का प्रकोप बना रहता है। औद्योगिक केन्द्रों को पानी की आवश्यकता होती है जबकि राजस्थान में पीने का पानी ही पर्याप्त पूर्ति न हो सकने के कारण उद्योगों की स्थापना में कठिनाई आती है। अब तो जल प्रदाय योजनाओं के कारण स्थिति कार्या सुधर गयी है।
- **परिवहन के साधनों का अभाव** – राजस्थान में यातायात व संचार व्यवस्था की भी पर्याप्त व्यवस्था न होने से, उद्योगों की स्थापना न हो सकी। 1951 में सड़को की कुल लम्बाई केवल 18,300 मील थी। प्रति 100 मील में 5.35 मील कच्ची–पक्कीं सड़क थी। संचार व्यवस्था की दुर्दशा इस बात से स्पष्ट है कि 247 किलोमीटर में एक पोस्ट ऑफिस तथा 1902 किलोमीटर में एक तारघर औसत आता था। शीघ्रगामी परिवहन के साधनों के अभाव में औद्योगीकरण की कल्पना बेकार थी। 2000–01 तक तो परिवहन एवं संचार व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। राज्य में सभी प्रकार की सड़कों की लम्बाई 153734 किलोमीटर है। फिर भी मांग को देखते हुए अभाव है। कोटा–चित्तौड़गढ़, जयपुर–सवाई माधोपुर, दिल्ली–अहमदाबाट में ब्रॉडगेज लाइन बनने से विकास तेज हुआ है।
- **कच्चे माल की पूर्ति** – राजस्थान में उपर्युक्त कठिनाइयों के अतिरिक्त औद्योगीकरण की मुख्य बाधा कच्चे माल की पूर्ति का न होना भी रही है। अधिकांश भाग मरुस्थली होने, सिचाई साधनों की कमी

आदि से व्यावसायिक फसलों की उत्पत्ति कम हो रही है, अब उनके उत्पादन में वृद्धि हो रही है। खनिजों पर आधारित उद्योगों का विकास भी कच्चे माल की पूर्ति में वृद्धि से ही सम्भव हो रहा है।

- **संकुचित बाजार** राजस्थान की जनता गरीब है और उनका जीवन–स्तर बहुत नीचा है, उनकी औद्योगिक वस्तुओं के लिए मांग होने के कारण भी उद्योगपति जोखिम उठाने में हिचकिचाते हैं। अब तो परिवहन के साधनों के विकास से बाहर माल भेजने व मंगवाने की सुविधायें बढ़ी हैं। आन्तरिक मांग भी बढ़ी है।
- **प्रशिक्षित व तकनीकी श्रमिकों का अभाव** – राजस्थान में उद्योगों के लिए प्रशिक्षित श्रमिकों तथा तकनीकी कर्मचारियों की कमी भी औद्योगीकरण की प्रमुख बाधा रही है। यद्यपि अब तकनीकी शिक्षा व प्रशिक्षण के लिये काफी सुविधायें उपलब्ध कर दी गई हैं, फिर भी दूसरे राज्यों से श्रमिकों को मंगाना पड़ता है।
- **ऋणों की वापसी में विलम्व एवं असमर्थता** – यद्यपि सरकार ने औद्योगिक वित्त संस्थाओं के माध्यम से बड़ी मात्रा में औद्योगिक ऋण प्रदान किये हैं किन्तु उनकी वापसी में विलम्ब तथा असमर्थता के कारण दिक्कतें आती हैं।
- **बिगड़ते औद्योगिक सम्बन्ध** – अखिल भारतीय स्तर पर बढ़ती महंगाई और श्रमिक संघों को हठधर्मी आदि के साथ–साथ उद्योगपतियों में शोषण की प्रवृत्ति से औद्योगिक सम्बन्ध बिगड़े और अन्यत्र की भांति राजस्थान भी हड़तालों, घेरावों, काम रोको, तालाबन्दी का शिकार हो रहा है जिससे औद्योगीकरण को धक्का पहुंचता है।

उद्योगों में राजकीय हस्तक्षेप के कारण

- कल्याणकारी राज्य हमारी सरकार का लक्ष्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। कल्याणकारी राज्य की विचारधारा यह स्पाह करती है कि राजनीतिक स्वातव्यता का उस समय तक कोई अर्थ नहीं होता है जब तक कि आर्थिक सुरक्षा एवं स्वतन्यता वहाँ के नागरिकों को न हो। आर्थिक सुरक्षा तथा स्वतन्त्रता के लिए राज्य को संरक्षक, सहयोगी एवं सलाहकार के रूप में कार्य करना होता है। इस प्रकार सरकार के द्वारा सामाजिक कल्याण में वृद्धि करने के उद्देश्य से भी औद्योगिक क्रियाओं में हस्तक्षेप किया जाने लगा है।
- आर्थिक विकास में तेजी इस प्रतिस्पर्धा युग में प्रत्येक राष्ट्र यह चाहता है कि उसका आर्थिक विकास तेजी से हो केवल निजी क्षेत्र के आधार पर विकास सम्भव नहीं है। इसलिए प्रत्येक सरकार आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष रुचि लेने लग गयी है और जीवन स्तर में वृद्धि के लिए प्रयत्नशील है। आर्थर लेविस ने लिखा है कि कोई भी राष्ट्र अपनी बुद्धिमान सरकार से सक्रिय सहयोग एवं प्रोत्साहन पाये बिना आर्थिक विकास नहीं कर सकता।"
- सन्तुलित आर्थिक विकास सन्तुलित आर्थिक विकास की आवश्यकता ने भी राजकीय हस्तक्षेप को अनिवार्य बना दिया है। निजी क्षेत्र केवल उन्हीं कार्यों को करना पसन्द करता है जिसमें उसको लाभ हो। इसलिए निजी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना एवं विकास उपलब्ध सुविधा क्षेत्र एवं विकसित बाजारों के निकट हुआ है। उनके द्वारा पिछड़े हुए क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। परिणामस्वरूप आर्थिक विकास सन्तुलित नहीं हुआ है। इसलिए राज्य का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है।
- दुर्लभ साधनों के वितरण एवं उपयोग की विवेकपूर्ण आवश्यकता प्रत्येक देश के साधन उसकी आवश्यकता से कम होते हैं अतः उनके विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है जिससे कि उनका दुरुपयोग न हो सके। इसके लिए जरूरी है कि राज्य साधनों के वितरण एवं उपयोग की नीतियों तय करें। इस आवश्यकता से भी राजकीय हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है।
- आधारभूत ढांचे का निर्माण औद्योगिक विकास के लिए देश के आधारभूत ढाँचे का पूर्ण रूप से विकसित होना जरूरी है। आधारभूत ढांचे में विद्युत, सिंचाई, यातायात, शिक्षा, बकिंग, बीमा तकनीको आदि

सम्मिलित हैं। इनके साधन सीमित होने के कारण इनको निजी क्षेत्र में देना सम्भव नहीं है। इनके विकास पर देश का विकास निर्भर करता है।

- आर्थिक नियोजन नियोजित अर्थव्यवस्था के पचाए नियन्त्रण आवश्यक हो गया है। देश का नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया अच्छी तरह निष्पादित कर सकदी हैं। एस एस खेरा ने लिखा या ती मान्यताओं के आधार पर या निष्कर्ष के में नियोजित को स्वीकार करता है उसे अनिवार्य रूप से अनेक प्रकार के उपक्रमाबर सक्रिय भागीदार और प्रवेश की ओर बढ़ना होता है अतः देश का नियोजित विकास करने के लिए सरकार को हमेशा इस तरफ सक्रिय रहना जरूरी है।
- केन्द्रीयकरण को रोकने के लिए केवल निजी क्षेत्र को ही उद्योगों की स्थापना से सम्बन्धित पूर्ण छूट देने पर देश में आर्थिक साधनों का केन्द्रीयकरण हो जायेगा। इसलिए क्षेत्र को सीमित करना आवश्यक है। लोक क्षेत्र का विकास करके शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोका जा सकता है। इसके लिए तृतीय योजना में कहा गया था– आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण और एकाधिकार की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए सरकार के पास जो निर्णायक शस्त्र है, वह है सरकारी क्षेत्र का द्रुत गति से विस्तार।"
- साधनों का हस्तान्तरण राजकीय हस्तक्षेप, नियन्त्रण एवं नियमन का उद्देश्य देश के उत्पादक साधनों को कम उपयोग से अधिक उपोयगी कार्यों में लगाना है। प्रशुल्क मूल्य मौद्रिक नीति द्वारा इस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है।
- अधिक जोखिमपूर्ण उद्योग जो उद्योग जोखिमपूर्ण हैं तथा जिसमें अधिक विनियोग करने को आवश्यकता है उन्हें लोक क्षेत्र में ही स्थापित किया जाना चाहिए। इनके लिए निजी क्षेत्र तैयार नहीं होता है जैसे बिजली, वायुयान, जहाज बाँध निर्माण, रेलवे आदि। इसके लिए सरकार को अपने अधीन उद्योग स्थापित करने पड़ते हैं। अतः राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक है।

निष्कर्ष

राज्य में औद्योगिक विकास की सम्भावनाएँ हैं। राज्य के द्वारा हाल ही में निर्धारित नीति के दूरगामी परिणाम होंगे। राज्य के पास स्थित संसाधन भी बहुत समृद्ध है। खनिज उत्पादन में राज्य का प्रमुख स्थान है। राजस्थान का 8 धात्विक व 25 अधात्विक खनिजों के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण स्थान है। पशुधन के क्षेत्र में भी राजस्थान का तीसरा स्थान है। राजस्थान नहर व अन्य बड़ी, मंझली व छोटी सिंचाई योजनाओं एवं कुओं के व्यापक विद्युतीकरण में राजस्थान व व्यावसायिक फसलों के उत्पादन में और अधिक वृद्धि होगी तथा इस क्षेत्र में भी राजस्थान अग्रणी राज्यों की श्रेणों में आ जायेगा। इस पर आधारित छोटे–छोटे उद्योग भी राज्य में खोले जा सकते हैं। पूंजीपतियों के बदलते हुए दृष्टिकोण में परिवर्तन के परिणामस्वरूप प्रांत में औद्योगिक विकास की अच्छी खासी सम्भावनाएँ दृष्टिगत होती हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत में आर्थिक पर्यावरण – प्रो. डी. आर. जाट, डॉ. वी. के. वशिष्ठ
2. राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण – डॉ. बी. पी. गुप्ता, आर. बी.डी. पब्लिशिंग
3. राजस्थान की अर्थव्यवस्था – डॉ. वी. के. ओझा, मनोज कुमार ओझा, आदर्श प्रकाशन जयपुर
4. औद्योगिक अर्थशास्त्र – संजय प्रकाशन जयपुर।
5. न्यूज पेपर – राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर
6. मैगजीन – इण्डिया टुडे, आऊट लुक।

❑❑❑